नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 227
दि. 21.05.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

केरल में नई सरकार का गठन पूरा, युवा मंत्रियों के साथ सतीशन कैबिनेट ने संभाली सत्ता, राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव

तिरुवनंतपुरम में लंबे राजनीतिक मंथन और सहयोगी दलों के बीच कई दिनों तक चली खींचतान के बाद आखिरकार V D Satheesan के नेतृत्व में नई सरकार का गठन पूरा हो गया है। मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे के साथ ही केरल में नई कैबिनेट ने औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया है। यह सरकार न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, बल्कि इसे राज्य की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत के रूप में भी देखा जा रहा है। इस नई सरकार के गठन के साथ ही राज्य में Kerala में लंबे समय से चले आ रहे सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कई दिनों तक चली चर्चाओं, अंदरूनी गुटबाजी और सहयोगी दलों के दबाव के बाद अंततः सभी मंत्रालयों का बंटवारा तय किया गया। खास बात यह है कि इस बार सरकार में युवा चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और कई नए विधायकों को पहली बार मंत्री पद मिला है।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह सरकार कांग्रेस नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा की वापसी का संकेत है, जिसने 2011 के बाद एक बार फिर सत्ता में प्रवेश किया है। इस बार की कैबिनेट में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि कुल 14 विधायक पहली बार मंत्री बने हैं, जिनमें से 6 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। इसे पार्टी की नई पीढ़ी को आगे लाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

सरकार गठन के दौरान यह भी साफ हुआ कि नेतृत्व ने युवाओं और नए चेहरों को प्राथमिकता देने का निर्णय जानबूझकर लिया है ताकि प्रशासन में नई ऊर्जा लाई जा सके। सरकार का उद्देश्य न केवल राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना है, बल्कि विकास की गति को भी तेज करना है।

नई कैबिनेट में महिलाओं को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वरिष्ठ नेता बिंदु कृष्णा को श्रम विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो राज्य में

श्रमिक नीतियों और रोजगार से जुड़े मुद्दों को संभालेगा। वहीं केए तुलसी को अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग दिया गया है, जो सामाजिक न्याय से जुड़े मामलों को देखेगा। इसके अलावा एम लिजू को आबकारी और सहकारिता जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी दी गई है।

कैबिनेट गठन के दौरान सबसे अधिक विवाद मत्स्य पालन विभाग को लेकर सामने आया। यह विभाग सहयोगी दलों के बीच लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा। अंततः यह विभाग इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के खाते में गया, और वीई अब्दुल गफूर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि इस फैसले पर कुछ सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने असंतोष भी जताया, लेकिन गठबंधन ने इसे संतुलन बनाए रखने का निर्णय बताया।

राजनीतिक समीकरणों के अनुसार मत्स्य विभाग तटीय समुदायों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, और इसी वजह से इस पर सभी सहयोगी दलों की नजर थी। कैबिनेट गठन के दौरान यह भी सुनिश्चित किया गया कि किसी एक समुदाय की उपेक्षा न हो और सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले।

इसी तरह स्वास्थ्य विभाग को लेकर कांग्रेस के भीतर भी लंबी चर्चा चली। वरिष्ठ नेताओं के बीच इस विभाग को लेकर खींचतान देखी गई। अंततः के मुरलीधरन को स्वास्थ्य और देवस्वम विभाग की जिम्मेदारी दी गई, जबकि एपी अनिल कुमार को राजस्व विभाग सौंपा गया। इस तरह सरकार ने अंदरूनी संतुलन बनाने की कोशिश की।

मुख्यमंत्री ने स्वयं कई महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हैं। इनमें वित्त, कानून, सामान्य प्रशासन और बंदरगाह विभाग शामिल हैं। यह निर्णय इस बात का संकेत माना जा रहा है कि सरकार इन विभागों पर सीधा नियंत्रण रखना चाहती है ताकि नीतिगत फैसलों में तेजी लाई जा सके।

गृह और सतर्कता विभाग की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला को दी गई है, जिन्हें प्रशासनिक अनुभव के लिए जाना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह नियुक्ति कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अन्य मंत्रियों में पीके कुन्हालीकुट्टी को उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग दिया गया है, जबकि पीसी विष्णुनाथ को पर्यटन, संस्कृति और सिनेमा विभाग सौंपा गया है। केएम शाजी को स्थानीय स्वशासन विभाग की जिम्मेदारी मिली है, जो राज्य के शहरी और ग्रामीण विकास की दिशा तय करेगा।

इस बीच विधानसभा के नए कार्यकाल की शुरुआत भी औपचारिक रूप से हो गई है। G Sudhakaran को 16वीं विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। उन्होंने राजभवन में राज्यपाल Rajendra Arlekar से शपथ ली। इसके बाद सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह नई सरकार कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। एक ओर यह युवा नेतृत्व और नई सोच का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं दूसरी ओर यह गठबंधन राजनीति के संतुलन का भी उदाहरण है। सरकार में शामिल विभिन्न दलों और समुदायों को साथ लेकर चलना इस कैबिनेट के लिए बड़ी चुनौती होगी।

विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि इस सरकार की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह अपने चुनावी वादों को कितनी तेजी से जमीन पर उतार पाती है। राज्य में बेरोजगारी, पर्यटन विकास, मछुआरा समुदाय की समस्याएं, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे सरकार के लिए प्राथमिकता रहेंगे।

राजनीतिक हलकों में इस बात पर भी चर्चा है कि युवा मंत्रियों की बड़ी संख्या सरकार को नई ऊर्जा तो देगी, लेकिन प्रशासनिक अनुभव की कमी एक चुनौती भी हो सकती है। ऐसे में वरिष्ठ नेताओं की भूमिका मार्गदर्शन और संतुलन बनाए रखने में अहम होगी।

कुल मिलाकर केरल में नई सरकार का गठन केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह राज्य की राजनीति में एक नए प्रयोग और नए संतुलन की शुरुआत है। आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि यह युवा और नई सोच वाली सरकार अपने वादों पर कितनी खरी उतरती है और राज्य की जनता की उम्मीदों पर कितना खरा प्रदर्शन कर पाती है।

तमिलनाडु की राजनीति में नया समीकरण, वीसीके ने टीवीके सरकार में शामिल होने पर विचार के संकेत दिए

चेन्नई में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, जहां Viduthalai Chiruthaigal Katchi (वीसीके) के अध्यक्ष Thol Thirumavalavan ने संकेत दिया है कि उनकी पार्टी Tamizhaga Vetri Kazhagam (टीवीके) के संभावित मंत्रिमंडल में शामिल होने के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में नए गठबंधन समीकरण बनने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। थिरुमावलवन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी को टीवीके नेतृत्व से एक नया राजनीतिक संकेत मिला है, जिसमें सहयोग और साझेदारी की संभावना पर बात की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वीसीके इस प्रस्ताव को गंभीरता से देख रही है, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी की राजनीतिक रणनीति और परिस्थितियों के मूल्यांकन के बाद ही लिया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, यह राजनीतिक हलचल उस समय और तेज हो गई जब टीवीके नेतृत्व की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि विद्रोही अन्नाद्रमुक विधायकों को कैबिनेट में शामिल नहीं किया जाएगा। इस फैसले को सरकार के भीतर स्थिरता बनाए रखने

की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि इससे संभावित अंदरूनी असंतोष और सत्ता संघर्ष की आशंका कम होती दिख रही है।

वीसीके पहले से ही टीवीके सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी, ताकि राज्य में राजनीतिक स्थिरता बनी रहे और केंद्र के हस्तक्षेप की संभावनाओं को सीमित किया जा सके। अब जब सीधे सरकार में शामिल होने की चर्चा सामने आई है, तो इसे गठबंधन राजनीति के अगले चरण के रूप में देखा जा रहा है।

थिरुमावलवन ने यह भी कहा कि उन्हें टीवीके के एक वरिष्ठ मंत्री Aadhav Arjuna से इस संबंध में सकारात्मक संदेश मिला है, जिसमें वीसीके को सरकार की संरचना में शामिल करने की इच्छा व्यक्त की गई है। उन्होंने इस पहल के लिए आभार भी जताया और कहा कि यह संकेत दोनों दलों के बीच बढ़ते राजनीतिक विश्वास को दर्शाता है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह घटनाक्रम तमिलनाडु की राजनीति में एक नए गठबंधन युग की शुरुआत का संकेत हो सकता है। लंबे समय से राज्य की राजनीति में प्रमुख दलों के बीच कड़ा मुकाबला रहा है, लेकिन अब छोटे और वैचारिक दलों की भूमिका सरकार गठन और स्थिरता में अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है।

विशेषज्ञों के अनुसार वीसीके का आधार मुख्य रूप से सामाजिक न्याय और दलित अधिकारों से जुड़ा हुआ है, जबकि टीवीके खुद को एक नई राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में दोनों दलों के बीच संभावित सहयोग से सरकार की नीतियों और सामाजिक एजेंडे पर भी असर पड़ सकता है।

हालांकि वीसीके नेतृत्व ने अभी यह साफ नहीं किया है कि वह पूरी तरह कैबिनेट में शामिल होगा या सीमित सहयोग तक ही रहेगा। पार्टी के भीतर इस मुद्दे पर चर्चा जारी है और संगठन के वरिष्ठ नेताओं से भी राय ली जा रही है।

राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि अगर वीसीके सरकार में शामिल होती है, तो इससे राज्य की सत्ता संतुलन में बड़ा बदलाव आ सकता है और विपक्षी दलों की रणनीति पर भी असर पड़ेगा। वहीं टीवीके के लिए यह कदम सरकार की स्थिरता और जनाधार बढ़ाने के लिहाज से अहम साबित हो सकता है।

फिलहाल सभी की नजरें वीसीके के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं, क्योंकि यह फैसला न केवल गठबंधन की दिशा तय करेगा, बल्कि आने वाले समय में तमिलनाडु की राजनीति की दिशा भी प्रभावित कर सकता है।

महिला वकीलों को 30% आरक्षण देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्यों से जवाब तलब

नई दिल्ली में कानूनी पेशे में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए Supreme Court of India ने केंद्र सरकार और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। यह मामला सरकारी पैनल, विधि अधिकारी पदों और कानूनी सहायता संस्थानों में महिला वकीलों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की मांग से जुड़ा है।

यह याचिका Ladli Foundation Trust द्वारा दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि देश के कानूनी ढांचे में महिलाओं की भागीदारी अभी भी अपेक्षाकृत कम है और उन्हें संस्थागत स्तर पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर राज्य स्तर तक सभी कानूनी और सरकारी पैनलों में महिला वकीलों के लिए न्यूनतम 30 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य किया जाए।

मामले की सुनवाई एक तीन सदस्यीय पीठ ने की, जिसमें मुख्य न्यायाधीश Justice Surya Kant, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली शामिल थे। पीठ ने याचिका को गंभीर मानते हुए केंद्र सरकार, सभी राज्यों और

केंद्र शासित प्रदेशों से विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है।

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता और Supreme Court Bar Association के अध्यक्ष Vikas Singh ने अदालत के सामने यह मुद्दा उठाया कि सरकारी पैनलों और विधि अधिकारी पदों पर महिला वकीलों की भागीदारी अभी भी काफी कम है। उन्होंने कहा कि कानूनी पेशे में लैंगिक असंतुलन को दूर करने के लिए ठोस नीतिगत कदम जरूरी हैं।

अदालत में यह भी बताया गया कि बार एसोसिएशन द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि कानूनी क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सीमित है, खासकर उन पदों पर जहां सरकारी मामलों की पैरवी या कानूनी सलाह देने की जिम्मेदारी होती है। इसी वजह से महिला वकीलों को संस्थागत स्तर पर अवसर बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

पीठ ने इस तर्क को गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को यह बताना होगा कि क्या वे इस तरह के आरक्षण या प्रतिनिधित्व नीति को लागू करने के पक्ष में हैं और यदि हां, तो इसे किस रूप में लागू किया जा सकता है।

इस मामले को भारतीय न्याय व्यवस्था में लैंगिक समानता और प्रतिनिधित्व के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अदालत इस दिशा में कोई ठोस दिशा-निर्देश देती है, तो यह पूरे देश की न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है।

वर्तमान में सरकारी पैनलों, लोक अभियोजन और विधि अधिकारी पदों पर महिलाओं की भागीदारी सीमित मानी जाती है, जबकि कानून के क्षेत्र में महिला वकीलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके बावजूद उच्च स्तर पर उनकी उपस्थिति अपेक्षाकृत कम बनी हुई है। अब सभी की नजर केंद्र सरकार और राज्यों के जवाब पर टिकी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा। यह मामला न केवल कानूनी पेशे में सुधार से जुड़ा है, बल्कि यह भारत में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण बहस को भी आगे बढ़ा रहा है।

तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान के संकेत, विरोध प्रदर्शन में आधे से ज्यादा विधायक रहे अनुपस्थित

All India Trinamool Congress के भीतर असंतोष और संगठनात्मक कमजोरी को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी के पहले बड़े विरोध प्रदर्शन में विधायकों की भारी अनुपस्थिति ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। बुधवार को विधानसभा परिसर में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के पास आयोजित इस प्रदर्शन में चुनाव के बाद कथित हिंसा और फेरीवालों पर कार्रवाई के विरोध में पार्टी विधायकों का एक गुट धरने पर बैठा, लेकिन कुल 80 विधायकों में से केवल 35 ही इसमें शामिल हुए। इस अनुपस्थिति ने पार्टी के भीतर संभावित दरार की अटकलों को और हवा दे दी है।

कोलकाता में हुए इस प्रदर्शन को पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत माना जा रहा है, क्योंकि सत्ता में 15 वर्षों तक रहने के बाद यह पहली बार है जब तृणमूल कांग्रेस को विधानसभा में विपक्ष की भूमिका में रहकर इस तरह का संगठित आंदोलन करना पड़ा है। राजनीतिक विश्लेषकों का

मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर विधायकों की गैरमौजूदगी केवल साधारण प्रशासनिक कारण नहीं हो सकती, बल्कि यह संगठन के भीतर गहरे असंतोष का संकेत भी हो सकती है।

प्रदर्शन में शामिल प्रमुख नेताओं में Shovandeb Chattopadhyay, नयना बनर्जी, कुणाल घोष और ऋतब्रत बनर्जी जैसे वरिष्ठ चेहरे मौजूद रहे। इन नेताओं ने राज्य में चुनाव के बाद कथित हिंसा और प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाई। धरने का उद्देश्य यह संदेश देना था कि पार्टी अब विपक्ष में रहकर जनता के मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाएगी।

हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने किसी भी तरह के विभाजन या टूट की बात से साफ इनकार किया है। शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने कहा कि कई विधायक अलग-अलग क्षेत्रों में संगठनात्मक कार्यों में व्यस्त थे और कुछ को सूचना देर से मिली, जिसके कारण वे प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने इसे संगठनात्मक असंतुलन या आंतरिक कलह से जोड़ने को गलत बताया।

लेकिन पार्टी के भीतर की चर्चाएं इस दावे से पूरी तरह सहमत नहीं दिखतीं। सूत्रों के अनुसार, हाल ही में Kolkata के कालीघाट क्षेत्र में हुई एक अहम बैठक के बाद कई विधायकों ने नेतृत्व शैली पर सवाल उठाए हैं। बैठक में यह राय सामने आई कि केवल रणनीतिक बैठकों और संगठनात्मक निर्देशों से पार्टी को मजबूत नहीं किया जा सकता, बल्कि जनता के बीच सक्रिय आंदोलन और जमीनी संघर्ष की जरूरत है।

सूत्रों के मुताबिक कुछ विधायकों ने यह भी कहा कि चुनावी हार के बाद पार्टी को सड़क पर उतरकर आक्रामक राजनीतिक रणनीति अपनानी चाहिए थी। उनका मानना है कि बंद कमरों में बैठकों और औपचारिक चर्चाओं से पार्टी का जनाधार दोबारा नहीं लौटेगा। इस तरह की राय ने नेतृत्व और विधायकों के बीच विचारों के अंतर को उजागर कर दिया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि किसी भी बड़े दल में चुनावी हार के बाद इस तरह की बहस सामान्य होती है, लेकिन जब विधायकों की बड़ी संख्या सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए, तो इसे पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 80 में से केवल 35 विधायकों की उपस्थिति यह संकेत देती है कि संगठनात्मक स्तर पर संवाद और समन्वय की कमी बनी हुई है।

हालांकि पार्टी नेतृत्व का दावा है कि संगठन पूरी तरह एकजुट है और सभी विधायक विभिन्न स्तरों पर अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं। उनका कहना है कि प्रदर्शन में कम उपस्थिति का मतलब असंतोष नहीं, बल्कि अलग-अलग जिम्मेदारियों का निर्वहन है। पार्टी के अनुसार आने वाले समय में संगठनात्मक बैठकों और जनसंपर्क कार्यक्रमों के जरिए स्थिति को और मजबूत किया जाएगा।

इसके बावजूद राजनीतिक गलियारों में यह सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या यह केवल अस्थायी असंतोष है या फिर All India Trinamool Congress के भीतर किसी बड़े राजनीतिक पुनर्गठन की शुरुआत। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष में आने के बाद संगठन के भीतर शक्ति संतुलन और नेतृत्व शैली को लेकर मतभेद स्वाभाविक रूप से उभरते हैं, लेकिन यदि इन्हें समय रहते नहीं संभाला गया तो यह भविष्य में गंभीर राजनीतिक चुनौती बन सकते हैं।

फिलहाल पार्टी की नजर आगामी रणनीतिक बैठकों और जन आंदोलनों पर है। नेतृत्व यह दिखाने की कोशिश में है कि संगठन पूरी तरह एकजुट है और विपक्ष की भूमिका को मजबूती से निभाने के लिए तैयार है। लेकिन अंदरूनी घटनाक्रम यह संकेत दे रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर सब कुछ उतना सहज नहीं है, जितना सार्वजनिक रूप से दिखाया जा रहा है।

संपादकीय

जन-सुरक्षा व पशु-कल्याण के बीच हो संतुलन

इसमें दो राय नहीं कि स्थानीय निकायों द्वारा आवारा कुत्तों को हटाने के संबंध में विगत में दिए अपने निर्देशों को नरम न करने का सर्वोच्च न्यायालय का हालिया निर्णय, बिगड़ते जन-सुरक्षा संकट में एक आवश्यक हस्तक्षेप है। हाल के वर्षों में, देश भर में स्थानीय प्रशासन व निकाय कुत्तों के काटने की घटनाओं में लगातार हो रही चिंताजनक वृद्धि को रोकने में विफल ही रहे हैं। ऐसे में शासन व प्रशासन स्तर पर इस समस्या के निराकरण की कोई सार्थक पहल न होते देख ही, शीर्ष अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अनुसार, साल 2023 में तीस लाख से अधिक कुत्तों के काटने के मामले दर्ज किए गए थे। उसके अगले साल 2024 में रोकथाम के कोई ठोस प्रयास न होने के कारण 37 लाख मामले दर्ज किए गए। आंकड़े बता रहे हैं कि औसतन प्रतिदिन दस हजार घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं कई राज्यों व शहरों में इन घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। हाल ही में सामने आए केरल के आंकड़ों के अनुसार, वहां एक साल के भीतर ही 3.6 लाख से अधिक कुत्तों के काटने के मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी दिल्ली से सटे नोएडा में कुछ ही महीनों में हजारों शिकायतों के बाद हॉटस्पॉट की पहचान की गई। इन शिकायतों में स्कूलों के पास उनका जमावड़ा होना, चलने में असमर्थ बुजुर्ग नागरिकों का शिकार बनना व आम नागरिकों के आवारा कुत्तों के भय में जीने के मामले उजागर हुए हैं। दरअसल, विगत में भी इस संकट के कारगर समाधान के लिये शीर्ष अदालत ने सख्त निर्देश दिए थे। स्थानीय नगर निगम व नगर पालिकाओं की जवाबदेही तय की थी कि कुत्तों को शेल्टर होम ले जाकर उनकी नसबंदी की जाए और टीकाकरण किया जाए। लेकिन इस दिशा में कारगर पहल होती नजर नहीं आई। वहीं तसवीर का दूसरा पहलू है कि यह संकट समाज और संस्थाओं द्वारा जानवरों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार में परेशान करने वाली विफलता को भी दर्शाता है।

पिछले दिनों चंडीगढ़ से एक स्तब्धकारी घटना ने हर किसी संवेदनशील व्यक्ति को विचलित किया,जब एक अज्ञात व्यक्ति ने एक पिल्ले को धधकते तंदूर में फेंककर जिंदा जला दिया। ऐसे शर्मनाक कृत्य उस भयावह क्रूरता को उजागर करते हैं, जो सार्वजनिक चर्चाओं में उजागर नहीं होती। इस घटना ने इन जीवों की दयनीय स्थिति को ही उजागर किया। वहीं भूख से बिलबिलाते कुत्तों द्वारा कथित तौर पर अपने ही बच्चों को खाने के मामले भी शामिल हैं। शीर्ष अदालत की इस टिप्पणी से सहमत हुआ जा सकता है कि जानवरों के साथ मानवीय व्यवहार का मतलब नागरिकों की सुरक्षा की अनदेखी करना नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ ही जन सुरक्षा को पशु कल्याण की उपेक्षा का बहाना भी नहीं बनाया जा सकता है। निस्संदेह, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानूनी रूप से जानवरों को स्थानांतरित करने पर दिए गए जोर के साथ अब आश्रय स्थलों, नसबंदी केंद्रों, टीकाकरण अभियानों और पशु चिकित्सा सुविधाओं में अधिक निवेश करने की सख्त जरूरत है। निश्चय ही यह चुनौती एक जटिल विषय है। सही मायनों में चुनौती यह भी है कि एक मानवीय, जवाबदेह और प्रभावी आवारा पशु प्रबंधन व्यवस्था का निर्माण किया जाए, जो नागरिकों और कुत्तों , दोनों के हितों की रक्षा कर सके। हमेशा से ही कुत्ते की गिनती मनुष्य के वफादार साथी के रूप में की जाती रही है। सदियों से दोनों एक साथ रहे हैं। उन कारणों की भी पड़ताल की जानी चाहिए, जिनके चलते कुत्ते अचानक आक्रामक व्यवहार दिखाने लगे हैं। निश्चय ही बढ़ता तापमान बदलते मौसमों के प्रति संवेदनशील इन जीवों को बेचैन किए हुए है। भूख व आश्रय के अभाव से उपजे असुरक्षाबोध ने भी उन्हें आक्रामक बनाने में भूमिका निभायी है। ऐसे में पशु प्रेमी संगठनों और स्थानीय प्रशासन को मिलकर इस संकट का कारगर समाधान निकालना होगा। ये समाधान सिर्फ सरकार या स्थानीय निकायों के बूते होना संभव नहीं है। पशु प्रेमियों की बड़ी पहल के परिणाम बदलाव लाने में सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं।

संधियों के टिकाऊ ढांचे से डीलमेकिंग की डगमग डगर तक

> “ दुनिया अब टिकाऊ संधियों और संस्थागत ढांचों के तहत परस्पर नहीं जुड़ी है। नियम आधारित व्यवस्था से सौदेबाजी की ओर बढ़ी है। रियलपॉलिटिक में महाशक्तियों का दोहरा खेल जारी है। आर्थिक संबंध भी व रणनीतिक शत्रुता भी। मल्टी अलाइनमेंट के इस दौर में दीर्घकालिक स्थिरता लाना जरूरी है।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की वैश्विक व्यवस्था संधियों और संस्थागत ढांचों पर टिकी थी। ब्रेटन वुड्स वित्तीय ढांचे से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक, सब कुछ नियम-आधारित था। यह व्यवस्था आदर्शवादी थी, जहां कानून और संधियां स्थायित्व देती थीं। लेकिन आज वह ढांचा बिखर चुका है। उसकी जगह आ गई है रियलपॉलिटिक—जहां स्थायी प्रतिबद्धताओं की जगह तात्कालिक सौदेबाजी और लचीले हितों का जाल है। साल 2024-25 में यूक्रेन युद्ध, गाज़ा संकट और ताइवान पर बढ़ते तनाव ने यह साफ कर दिया कि नियमों की दुनिया अब केवल कागज़ पर है।

दुनिया कठोर किलों से ‘लाउंज कूटनीति’ की ओर बढ़ी है। शीत युद्ध के नाटो और वारसा पैक्ट जैसी संस्थाएं कठोर थी, उनका उल्लंघन नहीं होता था। साल 1991 में सोवियत पतन के बाद उभरे जी-20, एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंच जानबूझकर गैर-बाध्यकारी रखे गए। वर्ष 2024 की ब्रिक्स शिखर बैठक में सऊदी अरब और ईरान की सक्रिय भागीदारी ने दिखाया कि यह मंच अब ‘आ ला कार्टे’ कूटनीति का प्रतीक है। देश अपनी सुविधा से आते-जाते हैं। स्थायी प्रतिबद्धता नहीं, सुविधानुसार साझेदारी।

मौजूदा विश्व में व्यापार और युद्ध का अजीब संगम सामने है। इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लक्षण है निहित सहनशीलता। अमेरिका-चीन तनाव के बावजूद व्यापार जारी है। साल 2025 में अमेरिकी टेक कंपनियों ने चीन से 70 फीसदी से अधिक रेयर अर्थ एलिमेंट्स आयात किए, जबकि वाशिंगटन बीजिंग को ‘रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी’ कहता रहा। पुरानी दुनिया में यह आत्मघाती होता, पर आज इसे आवश्यक लागत माना जाता है। यह विरोधाभास बताता है कि आपसी आर्थिक संबंध और रणनीतिक शत्रुता अब एक साथ चल रही हैं।

कूटनीति अब औपचारिक संधियों से नहीं, बल्कि फोन कॉल से तय होती है। मसलन, भारत-रूस तेल व्यापार पर अमेरिका का टैरिफ-2024 में एक कॉल में 50 फीसदी से घटकर 18 फीसदी। यही दोहरा खेल अमेरिका रूस के साथ भी खेल रहा है-पुतिन से दोस्ताना संवाद और साथ ही यूक्रेन को गुप्त मदद। वर्ष 2025 में व्हाइट हाउस और क्रेमलिन के बीच हुई ‘टेलीफोनिक डिप्लोमेसी’ ने दिखाया कि मौखिक प्रतिबद्धताएं औपचारिक दस्तावेज़ों से अधिक प्रभावी हो गई हैं।

अमेरिका वैसे तो पाकिस्तान को आतंकवाद पर कोसता है, लेकिन 2024–25 में उसे 2.5 अरब डॉलर की सहायता भी दी। भारत को सीमित रखने का यही तरीका है। चीन को रोकने के लिए भारत जरूरी है, फिर भी पाकिस्तान को मोहरे की तरह जीवित रखा जाता है। यह दोहरा रवैया बताता है कि सिद्धांतों की जगह केवल रणनीतिक उपयोगिता बची है। मित्र और मोहरा-दोनों एक साथ। नयी वैश्विक व्यवस्था के तहत दोहरे खेल की एक और मिसाल यह कि ताइवान को 2025 में 14 अरब डॉलर का हथियार पैकेज मिला, लेकिन इसे बीजिंग से सौदेबाजी का औज़ार बताया गया। सवाल है, क्या अमेरिका सैनिकों को 9,500 मील दूर भेजेगा? जब सुरक्षा गारंटी भी सौदेबाजी का हिस्सा बन जाए, तो पुरानी लक्ष्मण रेखाएं मिट जाती हैं। यह दिखाता है कि महाशक्ति भी अब अपने वादों को लाभ-हानि के तराजू पर तौल रही है।

नया दौर मिनिलैटरलिज्म का है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो नियम-आधारित व्यवस्था का वास्तुकार था, अब खुद बहुपक्षवाद से पीछे हट चुका है। क्वाड, ऑकस और आई2यू2 जैसे छोटे, लचीले समूह उभरे हैं। साल 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने ऑकस के तहत परमाणु पनडुब्बी समझौते को आगे बढ़ाया, जबकि आई2यू2 ने खाद्य सुरक्षा पर सहयोग किया। यह ‘मिनिलैटरलिज्म’ बताता है कि बड़ी संधियों की जगह छोटे-छोटे गठजोड़ ही भविष्य है।

भारत इस तरल यानी निरंतर बदलते माहौल में बहु-संरेखण का उदाहरण है। यह रणनीति मल्टी अलाइनमेंट की है। भारत ब्रिक्स और एससीओ में सक्रिय है, साथ ही क्वाड का स्तंभ भी। रूस से ऐतिहासिक संबंध बनाए रखते हुए अमेरिका के टैरिफ और पाकिस्तान नीति को संतुलित करता है। साल 2024–25 में भारत ने रूस से तेल आयात बढ़ाया, साथ ही अमेरिका से रक्षा सहयोग भी गहरा किया। यह रणनीतिक हेजिंग भारत की संप्रभुता का नया मानक है।

बीते दौर के संस्थागत किले कठोर थे, पर टिकाऊ थे। वहीं आज की निहित सहनशीलता नाजुक है- किसी गलत गणना से ढह सकती है। साल 2024 में गाज़ा युद्ध और 2025 में यूक्रेन मोर्चे पर बढ़ते तनाव ने दिखाया कि मानवीय पीड़ा अब स्वीकार्य कीमत बन गई है। नीति-निर्माताओं के लिए चुनौती अब नए किलों के निर्माण की नहीं, बल्कि इस लेन-देनवादी राजनीति को दीर्घकालिक संयम में बदलने की है। वर्तमान सौदेबाजी की दुनिया बिना किसी निश्चित दिशा के बह रही है। संधियों की स्याही से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों के बदलते समीकरणों से संचालित हो रही है। यह व्यवस्था लचीली है, पर नाजुक भी। नीति-निर्माताओं के लिए असली चुनौती है-तात्कालिक सौदेबाजी को दीर्घकालिक स्थिरता में बदलना। जब तक यह नहीं होता, रियलपॉलिटिक का यह नया युग महाशक्तियों के दोहरे खेल और छोटे-छोटे क्लबों की राजनीति से ही परिभाषित रहेगा।

प्रेरणा

भक्ति की असली दौलत

मनुष्य का जीवन अनेक इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और उपलब्धियों के पीछे भागते हुए बीत जाता है। कोई धन कमाने में सुख खोजता है, कोई प्रतिष्ठा पाने में, तो कोई अपने वैभव और सामर्थ्य के प्रदर्शन में। संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें और उसका सम्मान करें। यही भावना धीरे-धीरे मनुष्य के भीतर यह विश्वास पैदा कर देती है कि हर वस्तु का मूल्य धन से आंका जा सकता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन का सत्य इससे बिल्कुल अलग है। वहां बाहरी चमक-दमक नहीं, बल्कि हृदय की सच्चाई और भावना का महत्व होता है। ईश्वर के दरबार में मनुष्य की संपत्ति नहीं, उसकी भक्ति और निष्कपट प्रेम को देखा जाता है।

भारतीय संत परंपरा में अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन और शिक्षाओं से यह बताया कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखावे से नहीं, बल्कि सरलता और समर्पण से होकर जाता है। संत वल्लभाचार्य भी ऐसे ही महान संतों में गिने जाते हैं। उन्होंने अपने उपदेशों और आचरण से लोगों को यह समझाया कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें अहंकार का लेश न हो और प्रेम पूरी तरह से समर्पित हो।

एक बार उनके पास एक अत्यंत धनी शिष्य आया। उसके पास अपार धन-संपत्ति थी। महंगे वस्त्र, कीमती आभूषण और सेवकों की लंबी कतार उसके वैभव का परिचय देती थी। वह अपने गुरु का बहुत सम्मान करता था, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं यह भावना भी थी कि धन के बल पर वह ईश्वर को अधिक प्रसन्न कर सकता है। उसने संत वल्लभाचार्य से पूछा, “गुरुदेव, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए सबसे मूल्यवान भेंट क्या हो सकती है? क्या सोने-चांदी के आभूषण, बहुमूल्य रत्न, विशाल मंदिर या बड़े यज्ञ सबसे श्रेष्ठ भेंट हैं?”

उसके प्रश्न में जिज्ञासा कम और अपने वैभव पर गर्व अधिक झलक रहा था। वह मानता था कि जितनी बड़ी भेंट होगी, उतना अधिक ईश्वर प्रसन्न होंगे। संत वल्लभाचार्य उसके मन की स्थिति समझ गए। उन्होंने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। वे मुस्कराए और बोले, “चलो, आज तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अनुभव से देते हैं।”

वे अपने शिष्य को लेकर नगर के बाहरी हिस्से में बसे एक छोटे से गांव की ओर चल पड़े। वहां एक साधारण गृहस्थ का छोटा-सा घर था। मिट्टी की दीवारें, साधारण छप्पर और सीमित साधन देखकर स्पष्ट हो रहा था कि परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं था। फिर भी जब संत वल्लभाचार्य वहां पहुंचे तो पूरे परिवार के चेहरे पर अद्भुत प्रसन्नता छा गई। गृहस्थ और उसकी पत्नी ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। घर में जो थोड़ा-बहुत भोजन था, वही अत्यंत श्रद्धा से परोसा गया। बच्चों के चेहरे पर भी सम्मान और आनंद दिखाई दे रहा था।

उस परिवार ने कहीं भी यह अनुभव नहीं होने दिया कि उनके पास साधन कम हैं। उनके व्यवहार में इतनी आत्मीयता थी कि वहां बैठते ही वातावरण पवित्र और शांत लगने लगा। वे बार-बार यही कहते रहे कि “आज हमारा घर धन्य हो गया कि संत हमारे यहां आए।” भोजन साधारण था, लेकिन उसमें प्रेम और श्रद्धा का स्वाद इतना गहरा था कि वह किसी राजभोज से कम नहीं लग रहा था।

धनी शिष्य यह सब देख रहा था। उसके मन में अनेक विचार उठ रहे थे। वह सोच रहा था कि जिन लोगों के पास स्वयं के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं, वे इतनी प्रसन्नता और श्रद्धा के साथ अतिथि-सत्कार कैसे कर सकते हैं। वहां न कोई प्रदर्शन था, न किसी प्रकार का अहंकार। केवल सच्चा प्रेम और भक्ति थी।

कुछ समय बाद संत वल्लभाचार्य अपने शिष्य के साथ वहां से लौटने लगे। रास्ते में उन्होंने शिष्य से पूछा, “तुम्हें उस घर में सबसे विशेष क्या दिखाई दिया?”

शिष्य कुछ क्षण शांत रहा। फिर बोला, “गुरुदेव, उनके पास धन नहीं था, वैभव नहीं था, फिर भी उनके भीतर अद्भुत संतोष और श्रद्धा थी। उन्होंने जो भी दिया, पूरे मन से दिया। उनके व्यवहार में दिखावा बिल्कुल नहीं था।”

संत वल्लभाचार्य मुस्कराए और बोले, “यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। ईश्वर को सबसे प्रिय वही भेंट होती है जिसमें मन की सच्चाई और प्रेम हो। यदि किसी के पास थोड़ा है और वह भी श्रद्धा से अर्पित करता है, तो उसका मूल्य अनंत हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति करोड़ों की भेंट भी अहंकार और प्रदर्शन के साथ दे, तो वह भीतर से खोखली रह जाती है।”

उन्होंने आगे कहा, “भक्ति का मूल्य बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि अंतःकरण की पवित्रता से तय होता है। ईश्वर को धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समस्त सृष्टि उन्हीं की है। उन्हें केवल प्रेम चाहिए। जब मनुष्य बिना स्वार्थ, बिना अहंकार और बिना प्रदर्शन के समर्पण करता है, तभी उसकी भक्ति सच्ची कहलाती है।”

शिष्य की आंखें झुक गईं। उसे महसूस हुआ कि अब तक वह भक्ति को भी धन और वैभव की दृष्टि से देख रहा था। उसे लगा था कि महंगी वस्तुएं चढ़ाकर वह ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है, लेकिन आज उसे समझ आया कि ईश्वर के लिए सबसे बड़ी भेंट मन की निष्कपटता है। यह कथा केवल उस शिष्य की नहीं, बल्कि आज के समाज की भी सच्चाई है। आधुनिक जीवन में धर्म और भक्ति भी कई बार प्रदर्शन का माध्यम बन गए हैं। लोग बड़े-बड़े आयोजन करते हैं, विशाल दान देते हैं, लेकिन यदि उनके भीतर करुणा, विनम्रता और सच्चा प्रेम नहीं है, तो वह सब केवल बाहरी आडंबर बनकर रह जाता है। दूसरी ओर, कोई गरीब व्यक्ति यदि सच्चे मन से एक दीपक भी जलाता है, तो उसकी भक्ति अधिक प्रभावशाली हो सकती है। ईश्वर कभी मनुष्य की आर्थिक स्थिति नहीं देखते। वे यह देखते हैं कि मनुष्य का हृदय कितना निर्मल है। जिस मन में दया, सेवा, करुणा और प्रेम होता है, वही मन ईश्वर के सबसे निकट होता है। यही कारण है कि संतों ने हमेशा सरलता और विनम्रता को भक्ति का आधार माना है। मनुष्य जब अहंकार छोड़ देता है, तभी उसके भीतर सच्ची भक्ति का जन्म होता है। अहंकार मनुष्य को स्वयं से भर देता है, जबकि भक्ति मनुष्य को ईश्वर से जोड़ती है। दोनों साथ नहीं चल सकते। जहां अहंकार होगा, वहां प्रेम नहीं टिकेगा, और जहां प्रेम नहीं होगा, वहां भक्ति केवल औपचारिकता बनकर रह जाएगी।

संत वल्लभाचार्य की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। जीवन में चाहे कितना भी धन, पद या प्रतिष्ठा क्यों न मिल जाए, मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर के सामने सबसे बड़ा मूल्य उसके हृदय की सच्चाई का है। प्रेम, श्रद्धा और निष्कपट भावना से किया गया छोटा-सा समर्पण भी अनमोल बन जाता है। यही भक्ति की असली दौलत है, और यही वह मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से शांत, विनम्र और वास्तव में समृद्ध बनाता है।

शुभेंदु सरकार के त्वरित निर्णयों से उभरता नया बंगाल

बंगाल में 69 वर्षों के अथक संघर्ष के बाद बनी शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार अपने चुनावी संकल्प पत्र के अनुरूप काम पर लग गई है। सत्ता परिवर्तन होते ही सभी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बंद करवाए गए। अवैध बूचड़खानों पर बुलडोजर एक्शन के आदेश जारी हुए। सभी विद्यालयों में अब सम्पूर्ण वंदेमातरम का गायन अनिवार्य कर दिया गया है। सड़कों पर नमाज व अन्य धार्मिक गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई है। सीमा पर फेंसिंग के लिए सीमा सुरक्षा बल को जगह दे दी गई है और सम्पूर्ण भूमिहस्तांतरण निर्णय के 45 दिन में पूरा हो जाएगा। चिकन नेक क्षेत्र केंद्र को सौंप दिया गया है। धार्मिक आधार पर चलने वाली योजनाएं जैसे इमामों को वेतन बंद कर दिया गया है। आर.जी.कर केस की फाइल दोबारा खुलने के आदेश हो गए हैं। आयुष्मान भारत जैसी केंद्रीय जन कल्याण योजनाएं अब बंगाल पहुँच रही हैं। शुभेंदु सरकार की गति और संकल्प सिद्धि के प्रयासों से जुड़े निर्णयों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगा है। हालत यह हो गई है पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का डायमंड हार्बर मॉडल का पुष्पा "जहागीर खान" बहाना बनाकर फलटा विधानसभा उपचुनाव में ठीक उसी समय पलटा मारकर कर भाग गया जब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार को विजयी बनने के लिए रोड शो निकाल रहे थे। यह वही क्षेत्र है जहां विधानसभा चुनावों के दौरान ईवीएम मशीन पर भाजपा के चुनाव चिन्ह के आगे काला टेप लगा दिया गया था। यूपी के एक तेजतर्रार पुलिस अफसर अजय पाल शर्मा की आब्जर्वर के रूप में नियुक्ति हुई थी जिसके बाद जहांगीर खान ने पोस्टर जारी करके अपने आप को पुष्पा बताने की जुर्रत की थी। आज वही तथाकथित पुष्पा चुनावी मैदान बीच में छोड़कर भाग खड़ा हुआ। यह भय बनाम भरोसे में भरोसे की एक और बड़ी जीत है। यह सब कुछ हिंदुओं की एकजुटता और उनके जागरण से ही संभव हो सका है अगर हिंदू समाज आगे भी इसी प्रकार एकजुट रहता है तो सनातन का अपमान करने व उन्हें भयभीत करने वाले लोग इसी प्रकार से स्वतः प्रेरणा से भागते रहेंगे।

बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के भगवावस्त्र धारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चरण स्पर्श किए थे और उनके शपथ ग्रहण में योगी जी ने अपना भगवा पटका उनके गले में डाला था तभी यह बात तय हो गई थी कि बंगाल भी उत्तर प्रदेश की तरह सांस्कृतिक पुनर्जागरण के मार्ग पर चलने वाला है। बंगाल में भी दंगाइयों व उत्पातियों का इलाज यूपी की ही तरह होगा। कोलकाता के जिस थाने पर दगांइयों ने हमला करने का प्रयास किया था वहां मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी खुद पहुंचे और पुलिस बलों का मनोबल बढ़ाते हुए दंगाइयों व उपद्रवियों के प्रति जीरो टालरेंस की नीति अपनाने को कहा। मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा कि पुलिस पहले ममता दीदी के गुंडों से डरती थी किंतु अब समय बदल चुका है।

शुभेंदु सरकार के बड़े निर्णयों में वर्ष 2021 के चुनावों के बाद राज्य में हुई राजनतिक हत्याओं व हिंसक घटनाओं की सभी फाइलें खोलना भी है जिसके कारण ममता दीदी इतनी अधिक भयभीत हो गयीं कि वह काला कोट पहनकर हाईकार्ट पहुंच गयीं और 2021 की हिंसा से ध्यान भटकाने के लिए 2026 के चुनावों के बाद घटी कुछ छुटपुट घटनाओं को सनसनीखेज बताने का असफल प्रयास किया। जब वह कोर्ट परिसर से बाहर निकलने लगीं तब वकीलों के एक बड़े समूह ने उन्हें घेर लिया और चोर -चोर के नारे लगाए।

बंगाल में अब सीबीआई तथा ईडी जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों का प्रवेश संभव हो गया है, जिससे वहां 69 वर्षों में हुए घोटालों की जांच में गति आएगी। ईडी ने टीएमसी के बड़े नेताओं को हिरासत में ले भी लिया है। शुभेंदु अधिकारी के 145 एकड़ जमीन बीएसफ को देने के ऐतिहासिक निर्णय से बांग्लादेशी घुसपैठ की रोकथाम में महत्वपूर्ण सफलता मिलने की आशा है क्योंकि बांग्लादेश से लगी हुई बंगाल की लंबी खुली सीमा से बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठिए आसानी प्रवेश कर लेते थे। अब सीमा पर तीव्रता के साथ फेंसिंग का कार्य होगा।

बंगाल में मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए धर्म के आधार पर चलने वाली सभी योजनाएं बंद कर दी गई हैं। नई सरकार ने वोटबैंक के पुराने ढर्रे को ध्वस्त करने के एजेंडे पर आगे बढ़ चुकी है। बंगाल कैबिनेट ने धर्म के आधार पर चलाई जा रही सभी वित्तीय सहायता योजनाओ को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया है। यह मात्र एक प्रशासनिक निर्णय नहीं अपितु बंगाल की राजनीतिक दिशा को बदलने वाला वैचारिक परिवर्तन है। चुनावी बिसात पर इमामों, मुअज्जिनों और पुरोहितों के लिए शुरू की गई मासिक भत्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बंगाल के खेल मंत्री नीशिथ प्रामाणिक ने कोलकाता के युवा भारती क्रीडांगन परिसर में लगी व लोगो वाली फुटबालर की आधी प्रतिमा को तोड़े जाने का आदेश दिया है, बंगाल सरकार की विभिन्न वेबसाइटो से भी इसे हटाया जा रहा है। दिसंबर 22 में अर्जेंटीना के फुटबॉलर मेसी के कार्यक्रम में मची भगदड़ और कुप्रबंधन की जांच की जाएगी। उस घटना की फाइलें खोलने के आदेश जारी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी व अन्य सभी सहयोगी मंत्री यह बात लगातार कह रहे हैं कि जिन लोगों ने बंगाल को लूटा और जनता के मन मे भय पैदा किया उन सभी पर कार्यवाही जरूर की जाएगी।

बंगाल में अब आयुष्मान भारत योजना सहित केंद्र सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं के लागू होने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। भाजपा ने बंगाल की महिलाओं से किए गए वादों को भी लागू करना भी आरंभ कर दिया है।

अभियान

जब हिमालय की गोद में सुनाई दी अमरत्व की कथा

हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां सदियों से भारतीय आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रही हैं। इन पर्वतों की नीरवता में एक ऐसा रहस्य छिपा है, जिसने करोड़ों लोगों की आस्था को जन्म दिया। इन्हीं बर्फीली वादियों के बीच स्थित है अमरनाथ की पवित्र गुफा, जहां हर वर्ष सावन के महीने में श्रद्धा का अथाह सागर उमड़ पड़ता है। कठिन पहाड़ी रास्ते, बर्फीली हवाएं, खतरनाक चढ़ाइयां और अनिश्चित मौसम भी भक्तों की आस्था को कमजोर नहीं कर पाते। क्योंकि शिवभक्तों का विश्वास है कि बाबा बर्फानी के एक दर्शन मात्र से मनुष्य के जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं और आत्मा को दिव्य शांति प्राप्त होती है।

अमरनाथ केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां भक्ति और विश्वास अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। यहां पहुंचने वाला हर व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह किसी साधारण जगह पर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव के दरबार में खड़ा है। जब श्रद्धालु “हर-हर महादेव” और “बम-बम भोले” के जयघोष के साथ कठिन यात्रा पूरी करते हैं, तब उनके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा लगता है मानो शिव स्वयं अपने भक्तों को अपने पास बुला रहे हों।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, यही वह पवित्र गुफा है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरता का रहस्य सुनाया था। कथा के अनुसार माता पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से पूछा कि आखिर आपके अमर होने का रहस्य क्या है। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि मृत्यु के पार का सत्य क्या है और संसार का निर्माण कैसे हुआ। माता पार्वती की जिज्ञासा सुनकर भगवान शिव ने उन्हें वह दिव्य ज्ञान देने का निश्चय किया, जिसे “अमर कथा” कहा जाता है। लेकिन यह कोई साधारण कथा नहीं थी। यह सृष्टि, जीवन और मृत्यु के सबसे गहरे रहस्य से जुड़ी हुई थी। भगवान शिव नहीं चाहते थे कि यह रहस्य कोई अन्य जीव सुन सके। इसलिए उन्होंने एक ऐसे स्थान की खोज की जहां पूर्ण एकांत हो। इसी उद्देश्य से वे माता पार्वती को लेकर हिमालय की ओर निकल पड़े।

कहा जाता है कि यात्रा के दौरान भगवान शिव ने अपने सभी प्रतीकों और साथियों का त्याग किया। पहलगाम में उन्होंने अपने प्रिय वाहन नंदी को छोड़ा। चंदनवाड़ी में अपने मस्तक का चंद्रमा उतार दिया। शेषनाग झील के पास गले के सर्पों को त्यागा और पंचतरणी में पांच तत्वों का विसर्जन किया। इसके बाद वे उस गुफा तक पहुंचे, जिसे आज अमरनाथ धाम कहा जाता है।

गुफा में प्रवेश करने से पहले भगवान शिव ने अग्नि प्रज्ज्वलित कर दी ताकि वहां कोई जीवित प्राणी न बच सके। इसके बाद उन्होंने माता पार्वती को अमर कथा सुनानी शुरू की। लेकिन मान्यता है कि गुफा में मौजूद कबूतरों का एक जोड़ा यह कथा सुन रहा था। अमर कथा सुनने के कारण वह कबूतर जोड़ा अमर हो गया। आज भी कई श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के दौरान सफेद कबूतरों के दर्शन को शिव की विशेष कृपा मानते हैं। भक्तों का विश्वास है कि यह वही अमर कबूतर हैं, जिन्होंने भगवान शिव की कथा सुनी थी।

अमरनाथ धाम का महत्व केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। प्राचीन ग्रंथों में भी इस तीर्थ की महिमा का वर्णन मिलता है। ‘नीलमत पुराण’ और ‘बृंगेश संहिता’ में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्तिभाव से बाबा बर्फानी के दर्शन करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। यहां तक कहा गया है कि अमरनाथ के दर्शन का फल काशी, प्रयागराज और नैमिषारण्य जैसे महान तीर्थों से भी अधिक माना गया है। यही कारण है कि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु अपनी सारी कठिनाइयों को भूलकर इस यात्रा पर निकल पड़ते हैं।

अमरनाथ गुफा की खोज को लेकर भी अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। पुराणों के अनुसार, प्राचीन काल में कश्मीर की घाटी जलमग्न थी। वहां एक विशाल झील हुआ करती थी। ऋषि कश्यप ने अपनी तपस्या और प्रयासों से उस जल को बाहर निकाला और घाटी को रहने योग्य बनाया। उसी समय महान तपस्वी ऋषि भृगु हिमालय की यात्रा पर निकले। यात्रा के दौरान उन्होंने इस रहस्यमयी गुफा को देखा। जब वे भीतर पहुंचे, तो वहां उन्होंने दिव्य हिम शिवलिंग के दर्शन किए। इसलिए ऋषि भृगु को बाबा बर्फानी का प्रथम दर्शन करने वाला माना जाता है। कहा जाता है कि ऋषि भृगु ने ही सबसे पहले लोगों को इस पवित्र गुफा के बारे में बताया था। धीरे-धीरे यह स्थान साधु-संतों और शिवभक्तों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया। समय बीतने के साथ अमरनाथ यात्रा का महत्व इतना बढ़ गया कि यह भारत की सबसे पवित्र और कठिन यात्राओं में गिनी जाने लगी। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी एक और कथा स्थानीय लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में बूटा मलिक नाम का एक मुस्लिम चरवाहा अपने पशुओं को चराने के लिए पहाड़ों की ओर गया था। वहां उसकी मुलाकात एक संत से हुई। संत ने उसे कोयले से भरा एक थैला दिया। बूटा मलिक जब घर पहुंचा और उसने वह थैला खोला, तो उसमें कोयले की जगह सोने के सिक्के थे। यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। वह तुरंत उस संत को धन्यवाद देने वापस लौटा, लेकिन वहां उसे कोई संत नहीं मिला। उसी स्थान पर उसे एक गुफा दिखाई दी। जब वह भीतर गया, तो उसने वहां दिव्य हिम शिवलिंग के दर्शन किए। बूटा मलिक ने गांव लौटकर लोगों को इस चमत्कारी गुफा के बारे में बताया। धीरे-धीरे यह समाचार दूर-दूर तक फैल गया और श्रद्धालुओं की यात्रा आरंभ हो गई।

इस कथा की सबसे सुंदर बात यह है कि भगवान शिव ने अपने दर्शन के लिए किसी धर्म या जाति का भेद नहीं किया। एक मुस्लिम चरवाहे को इस गुफा का माध्यम बनाकर उन्होंने यह संदेश दिया कि ईश्वर के लिए सबसे बड़ा धर्म प्रेम और भक्ति है। यही कारण है कि अमरनाथ यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि मानवता और आस्था का प्रतीक बन चुकी है। इतिहास में भी अमरनाथ धाम का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध इतिहासकार कल्हण द्वारा रचित ‘राजतरंगिणी’ में अमरेश्वर शिवलिंग का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि 11वीं शताब्दी में कश्मीर की रानी सूर्यमती ने यहां त्रिशूल और अन्य भेंट अर्पित की थीं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सदियों से यह स्थान श्रद्धा और भक्ति का केंद्र रहा है।

हर वर्ष जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, तब ऐसा लगता है मानो पूरा वातावरण शिवमय हो गया हो। हजारों श्रद्धालु अपने कंधों पर सामान और दिल में अटूट विश्वास लेकर कठिन रास्तों पर निकल पड़ते हैं। कोई पैदल चलता है, कोई घोड़े का सहारा लेता है, तो कोई वृद्धावस्था में भी बाबा के दर्शन की इच्छा लेकर यात्रा पूरी करता है। रास्ते में जगह-जगह भंडारे चलते हैं, जहां श्रद्धालुओं की सेवा की जाती है। यह दृश्य भारतीय संस्कृति की करुणा, सेवा और एकता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है।

अमरनाथ यात्रा केवल शरीर की परीक्षा नहीं, बल्कि मन और आत्मा की भी परीक्षा होती है। बर्फीले रास्तों पर चलते हुए श्रद्धालु जीवन की कठिनाइयों को समझते हैं। उन्हें एहसास होता है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं होता। धैर्य, विश्वास और समर्पण के बिना कोई भी आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त नहीं की जा सकती। जब श्रद्धालु गुफा के भीतर पहुंचकर बाबा बर्फानी के दिव्य स्वरूप के दर्शन करते हैं, तब उनकी आंखें स्वतः नम हो जाती हैं। उस क्षण उन्हें ऐसा लगता है मानो भगवान शिव स्वयं उनके सामने खड़े हों। सारी थकान, पीड़ा और चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। मन को ऐसी शांति मिलती है, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अमरनाथ की गुफा में बनने वाला हिम शिवलिंग भी अपने आप में एक रहस्य है। यह शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है और चंद्रमा की कलाओं के अनुसार घटता-बढ़ता है। श्रद्धालु इसे भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति मानते हैं। विज्ञान इसे प्राकृतिक प्रक्रिया कह सकता है, लेकिन भक्तों के लिए यह उनकी अटूट आस्था का प्रतीक है। आज के समय में जब मनुष्य भौतिक सुखों के पीछे भागते-भागते मानसिक तनाव और असंतोष से घिर गया है, तब अमरनाथ यात्रा उसे आत्मिक शांति का मार्ग दिखाती है। यह यात्रा सिखाती है कि सच्चा सुख धन और वैभव में नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति समर्पण में है।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में बड़ी प्रगति, 330 मीटर स्टील ब्रिज के अहम हिस्से का सफल निर्माण, फ्रेट कॉरिडोर पर तकनीकी उपलब्धि दर्ज

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत निर्माण कार्यों में एक और बड़ा तकनीकी मील का पत्थर हासिल किया गया है। गुजरात के भरूच जिले के त्रालसी गांव के पास पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) के ऊपर 330 मीटर लंबे स्टील ब्रिज का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें 130 मीटर लंबे महत्वपूर्ण स्पैन का सफलतापूर्वक लॉन्चिंग कार्य पूरा कर लिया गया है। यह वही सेक्शन है जो सूरत-वडोदरा रेलवे ट्रैक को क्रॉस करता है और इस पूरे प्रोजेक्ट को इंजीनियरिंग के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है।

इस ब्रिज की खास बात इसकी जटिल संरचना और विशाल पैमाना है। यह केवल एक साधारण पुल नहीं बल्कि तीन अलग-अलग स्पैन से मिलकर बना एक अत्याधुनिक स्टील स्ट्रक्चर है, जिसमें 100 मीटर + 130 मीटर का सतत (Continuous) स्पैन और 100 मीटर का सिम्पली सपोर्टेड स्पैन शामिल है। हाल ही में 130 मीटर लंबे स्पैन को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया, जिसका वजन लगभग 2900 मीट्रिक टन बताया गया है। यह पूरी तरह से उच्च तकनीक आधारित इंजीनियरिंग का उदाहरण है, जिसे जमीन से लगभग 14 मीटर की ऊंचाई पर अस्थायी ट्रेस्टल संरचनाओं के सहारे असेंबल किया गया और फिर विशेष हाइड्रोलिक जैकिंग सिस्टम के माध्यम से अपनी निर्धारित जगह पर सरकाया गया।

इस पूरे निर्माण में अत्याधुनिक तकनीक और सटीक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है। ब्रिज के निर्माण में 1,21,373 हाई स्ट्रेंथ टॉर-शियर टाइप बोल्ट लगाए गए हैं, जो इसकी मजबूती और दीर्घकालिक स्थिरता को सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा C5 सिस्टम की विशेष पेंटिंग का उपयोग किया गया है, जो इसे जंग और मौसम के प्रभाव से बचाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैटेलिक बेयरिंग का इस्तेमाल भी इसकी संरचनात्मक सुरक्षा को और मजबूत बनाता है। इंजीनियरों के अनुसार इस स्टील ब्रिज को लगभग 100 वर्षों की आयु को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, ताकि यह भविष्य की हाई-स्पीड रेल सेवाओं के लिए पूरी तरह सक्षम बना रहे। लॉन्चिंग प्रक्रिया भी बेहद तकनीकी और जोखिमपूर्ण रही। 130 मीटर लंबे इस हिस्से को सेमी-ऑटोमैटिक जैक सिस्टम की मदद से आगे बढ़ाया गया, जिसमें प्रत्येक जैक की क्षमता लगभग 250 टन तक पुशिंग की है। इस दौरान मैक-अलॉय बार्स का उपयोग कर पूरे स्ट्रक्चर को संतुलित और नियंत्रित रखा गया। निर्माण कार्य के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि फ्रेट कॉरिडोर पर चलने वाली मालगाड़ियों की आवाजाही न्यूनतम रूप से प्रभावित हो, जिसके लिए विशेष रूप से समन्वित ट्रैफिक ब्लॉक्स और सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई। परियोजना से जुड़े अधिकारियों के अनुसार यह ब्रिज मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है, क्योंकि यह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बिना किसी बाधा के पार करने की सुविधा देता है। अब तक इस कॉरिडोर में प्रस्तावित 28 स्टील ब्रिजों में से 17 पर काम चल रहा है, जबकि 14 ब्रिज केवल गुजरात क्षेत्र में ही सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। यह आंकड़ा इस बात का संकेत है कि परियोजना तेजी से अपने अंतिम चरणों की ओर बढ़ रही है। इस पूरे कॉरिडोर का निर्माण भारत में पहली बार हाई-स्पीड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की तकनीक के साथ किया जा रहा है। स्टील ब्रिजों की यह श्रृंखला न केवल इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का उदाहरण है, बल्कि यह भारत की आधुनिक परिवहन प्रणाली की दिशा में एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। परियोजना के पूरा होने के बाद मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा समय में भारी कमी आएगी और यह देश की सबसे तेज रेल सेवाओं में शामिल होगी। भरूच में पूरा हुआ यह 130 मीटर का स्पैन इस बात का प्रतीक है कि भारत अब जटिल और बड़े पैमाने की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को घरेलू विशेषज्ञता और आधुनिक तकनीक के बल पर सफलतापूर्वक पूरा करने की क्षमता रखता है। आने वाले महीनों में शेष स्पैन के निर्माण के साथ यह ब्रिज पूरी तरह तैयार हो जाएगा और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को एक नई गति और मजबूती प्रदान करेगा।

हिमाचल में खाद सब्सिडी विवाद गरमाया, कांग्रेस सरकार पर भाजपा का हमला, किसानों की लागत बढ़ने की आशंका

शिमला में डीएपी और एनपीके खाद पर दी जा रही अतिरिक्त सब्सिडी को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। 50 रुपये प्रति बोरी की अतिरिक्त सब्सिडी बंद करने के फैसले के बाद विपक्षी दल भाजपा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर सीधा हमला बोला है और इसे किसानों के हितों के खिलाफ बताया है। यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब राज्य की कृषि व्यवस्था पहले से ही प्राकृतिक आपदाओं, बढ़ती लागत और बाजार की अनिश्चितताओं के दबाव में है। विपक्ष का कहना है कि इस फैसले से किसानों और बागवानों की आर्थिक स्थिति और अधिक कमजोर हो सकती है। इस मुद्दे पर शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष Suresh Kashyap ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने ऐसा निर्णय लेकर किसानों के साथ विश्वासघात किया है। उनके अनुसार खाद पर दी जा रही सब्सिडी हटाने से सीधे तौर पर खेती की लागत बढ़ेगी और इसका असर लाखों किसान परिवारों पर पड़ेगा।

भाजपा नेता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में कृषि और बागवानी ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। यहां लगभग लाखों परिवार सीधे तौर पर खेती और बागवानी से जुड़े हुए हैं। ऐसे में खाद की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी भी उनके बजट पर बड़ा असर डालती है।

कश्यप के अनुसार किसान पहले ही कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दाम, मजदूरी की बढ़ती लागत, मौसम की अनिश्चितता और प्राकृतिक आपदाओं ने खेती को पहले ही मुश्किल बना दिया है। ऐसे में सब्सिडी में कटौती स्थिति को और चुनौतीपूर्ण बना देगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने इस फैसले को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट अधिसूचना जारी नहीं की है, लेकिन कृषि विभाग के अधिकारियों की ओर से यह संकेत दिए गए हैं कि आने वाले समय में खाद की नई खेप बढ़ी हुई कीमतों पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस स्थिति ने किसानों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यह फैसला वित्तीय दबाव के कारण लिया गया है या फिर यह कृषि क्षेत्र में किसी नई नीति का हिस्सा है। हालांकि सरकार की ओर से इस पर अभी विस्तृत स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। भाजपा सांसद ने दावा किया कि केंद्र सरकार की कई योजनाएं किसानों को सीधी आर्थिक सहायता प्रदान कर रही हैं। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, सिंचाई से जुड़ी योजनाएं और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाली योजनाएं शामिल हैं। उनका कहना है कि केंद्र की इन योजनाओं का लाभ तो मिल रहा है, लेकिन राज्य सरकार उनकी प्रभावी क्रियान्वयन में पीछे रह रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कई सहकारी समितियों और कृषि केंद्रों में खाद की उपलब्धता समय पर नहीं हो रही है, जिससे किसानों को सीजन के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खाद की कमी और कीमतों में बढ़ोतरी दोनों मिलकर किसानों के लिए दोहरी चुनौती बन गई हैं।

राजनीतिक स्तर पर यह मुद्दा अब तेज होता जा रहा है। भाजपा ने मांग की है कि डीएपी और एनपीके खाद पर 50 रुपये प्रति बोरी की अतिरिक्त सब्सिडी तुरंत बहाल की जाए। साथ ही किसानों को राहत देने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की जाए।

भाजपा ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया, तो पार्टी राज्यभर में आंदोलन शुरू करेगी। विपक्ष का कहना है कि किसानों की अनदेखी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। दूसरी ओर, सरकार की तरफ से यह तर्क दिया जा सकता है कि सब्सिडी नीति में बदलाव वित्तीय संतुलन और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए किया गया हो सकता है, लेकिन इस पर स्पष्ट सरकारी बयान का इंतजार है।

विशेषज्ञों का मानना है कि खाद सब्सिडी जैसे मुद्दे सीधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े होते हैं और इनका प्रभाव सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी कृषि आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ता है। अगर इनपुट लागत बढ़ती है, तो इसका असर खाद्य उत्पादन और बाजार कीमतों पर भी दिखाई देता है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में खाद सब्सिडी को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे में बदलता दिख रहा है।

भारत की ग्रीन एनर्जी क्रांति: 2030 तक 7 लाख एकड़ भूमि की जरूरत, 15 अरब डॉलर निवेश की संभावना

नई दिल्ली। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का तेजी से विस्तार अब देश की ऊर्जा नीति, भूमि उपयोग और औद्योगिक विकास का पूरा ढांचा बदलने की दिशा में बढ़ रहा है। इसी संदर्भ में रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर परामर्श कंपनी Colliers India की एक नई रिपोर्ट ने बड़ा अनुमान जारी किया है कि वर्ष 2030 तक सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार के लिए भारत को लगभग सात लाख एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। यह अनुमान इस बात का संकेत है कि आने वाले वर्षों में भारत में ऊर्जा उत्पादन केवल तकनीकी नहीं, बल्कि भू-आर्थिक (geo-economic) परिवर्तन का भी बड़ा केंद्र बनने जा रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार इस विशाल भूमि आवश्यकता को पूरा करने के लिए बड़े स्तर पर निवेश की जरूरत होगी, जो 10 से 15 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। यह निवेश केवल बिजली उत्पादन संयंत्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे जुड़े ट्रांसमिशन नेटवर्क, ग्रिड विस्तार, सब-स्टेशन, ऊर्जा भंडारण प्रणाली और ग्रीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास में भी खर्च किया जाएगा। इस प्रकार यह क्षेत्र एक संपूर्ण औद्योगिक इकोसिस्टम के रूप में विकसित होता दिखाई दे रहा है।

Colliers की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2030 तक भारत की सौर और पवन ऊर्जा क्षमता में 270 से 300 गीगावाट तक की अतिरिक्त वृद्धि संभव है। इसमें सबसे बड़ा योगदान सौर ऊर्जा का रहेगा, जिसके लिए लगभग 6.5 लाख एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी, जबकि शेष भूमि पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल की जाएगी। सौर परियोजनाओं के लिए बड़े और समतल भूभाग की जरूरत होती है, जबकि पवन ऊर्जा के लिए तटीय और ऊंचाई वाले क्षेत्र अधिक उपयुक्त माने जाते हैं।

भारत पहले ही नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर चुका है। रिपोर्ट के अनुसार देश की स्थापित ग्रीन एनर्जी क्षमता 250 गीगावाट को पार कर चुकी है, जो वर्ष 2015 में केवल लगभग 80 गीगावाट थी। यह तीन गुना से अधिक वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि भारत तेजी से पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम कर रहा है। अनुमान है कि मार्च 2026 तक यह क्षमता बढ़कर लगभग 275 गीगावाट तक पहुंच जाएगी, जिससे इस क्षेत्र की निरंतर गति स्पष्ट होती है।

हालांकि इस तेज विकास के साथ कई चुनौतियां भी सामने हैं। सबसे बड़ी चुनौती इतनी बड़ी मात्रा में भूमि का अधिग्रहण है, जिसमें कृषि भूमि, वन क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों के उपयोग से जुड़े सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा पर्यावरणीय मंजूरी, स्थानीय समुदायों की सहमति और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी प्रमुख बाधाएं बन सकती हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कुल परियोजना लागत का लगभग 10 से 12 प्रतिशत हिस्सा केवल भूमि और आवश्यक अनुमतियों पर खर्च होता है।

वित्तीय दृष्टि से यह क्षेत्र निवेशकों के लिए तेजी से आकर्षण का केंद्र बन रहा है। सौर ऊर्जा परियोजनाओं में प्रति मेगावाट लगभग 3 से 4 करोड़ रुपये और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में 8 से 9 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट तक निवेश की आवश्यकता होती है। इसके चलते जैसे-जैसे परियोजनाएं बढ़ेंगी, वैसे-वैसे इस क्षेत्र में कुल पूंजी निवेश भी तेजी से बढ़ेगा। अनुमान है कि 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कुल निवेश 110 से 120 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। वर्तमान में भारत में लगभग 146 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिनमें से 60 प्रतिशत से अधिक सौर ऊर्जा आधारित हैं। यह आंकड़ा इस बात को दर्शाता है कि भारत पहले ही अपने ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा चुका है और आने वाले वर्षों में यह गति और तेज होने की संभावना है। कोलियर्स इंडिया के सीईओ बादल याग्निक ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र केवल बिजली उत्पादन का माध्यम नहीं रहेगा, बल्कि यह भारत के औद्योगिक भविष्य का आधार बनेगा। उनके अनुसार ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सिस्टम और ऊर्जा भंडारण आधारित उद्योग इस परिवर्तन के प्रमुख हिस्से होंगे, जो देश की आर्थिक संरचना को नया आकार देंगे।

क्रूड ऑयल वायदा 139 रुपये फिसला: सोना वायदा में 226 रुपये और चांदी वायदा में 3401 रुपये की वृद्धि

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 187690.91 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 26902.63 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 160788.16 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का मई वायदा 38660 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2147.33 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 18588.33 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा सत्र के आरंभ में 158974 रुपये के भाव पर खूलकर, 160378 रुपये के दिन के उच्च और 157959 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 159080 रुपये के पिछले बंद के सामने 226 रुपये या 0.14 फीसदी की मजबूती के साथ 159306 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-गिनी मई वायदा 219 रुपये या 0.17 फीसदी बढ़कर 127441 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-पेटल मई वायदा 19 रुपये या 0.12 फीसदी बढ़कर 15956 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। सोना-मिनी जून वायदा 157362 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 158832 रुपये और नीचे में 157152 रुपये पर पहुंचकर, 307 रुपये या 0.19 फीसदी बढ़कर 158730 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-टेन मई वायदा प्रति 10 ग्राम 158433 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 159327 रुपये और नीचे में 157221 रुपये पर पहुंचकर, 158596 रुपये के पिछले बंद के सामने 244 रुपये या 0.15 फीसदी बढ़कर 158840 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

चांदी के वायदाओं में चांदी जुलाई वायदा सत्र के आरंभ में 267230 रुपये के भाव पर खूलकर, 274190 रुपये के दिन के उच्च और 266850 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 270119 रुपये के पिछले बंद के सामने 3401 रुपये या 1.26 फीसदी की तेजी के संग 273520 रुपये प्रति किलो हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी जून वायदा 3496 रुपये या 1.28 फीसदी की तेजी के संग 276805 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। जबकि चांदी-

▶▶ कमोडिटी वायदाओं में 26902.63 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 160788.16 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 18588.33 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 38660 पॉइंट के स्तर पर

माइक्रो जून वायदा 3510 रुपये या 1.28 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 276865 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

मेटल वर्ग में 3466.68 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मई वायदा 6.45 रुपये या 0.48 फीसदी बढ़कर 1344 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता मई वायदा 2.6 रुपये या 0.71 फीसदी की बढ़त के साथ 368.9 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम मई वायदा 95 पैसे या 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 385.35 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा मई वायदा 20 पैसे या 0.1 फीसदी घटकर 202 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 4708.46 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जून वायदा सत्र के आरंभ में 10083 रुपये के भाव पर खूलकर, 10104 रुपये के दिन के उच्च और 9780 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 139 रुपये या 1.39 फीसदी की गिरावट के साथ 9888 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जून वायदा 143 रुपये या 1.43 फीसदी औंधकर 9886 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। इनके अलावा नैचुरल गैस मई वायदा 300 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 301.4 रुपये और नीचे में 297.3 रुपये पर पहुंचकर, 299.4 रुपये के पिछले बंद के सामने 1.6 रुपये या 0.53 फीसदी बढ़कर 301 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मई वायदा 1.5 रुपये या 0.5 फीसदी की तेजी के संग 300.9 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मई वायदा सत्र के आरंभ में 993.9 रुपये के भाव पर खूलकर, 40 पैसे या 0.04 फीसदी की नरमी के साथ 990.2 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 9658.48 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 8929.86 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 2566.59 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 407.64 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 9.84 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 468.82 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 3033.54 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1667.65 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 0.71 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9918 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 61746 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 20408 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 306182 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 44667 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 9830 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 23896 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 78161 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 17773 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 31450 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स मई वायदा सत्र के आरंभ में 38660 पॉइंट पर खूलकर, 38660 के उच्च और 38660 के नीचले स्तर को छूकर, 44 पॉइंट बढ़कर 38660 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल जून 10000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 83.7 रुपये की गिरावट के साथ 745.6 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मई 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 15 पैसे के सुधार के साथ 6.1 रुपये हुआ।

सोना मई 170000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 4.5 रुपये की बढ़त के साथ 123 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मई 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 80 रुपये की बढ़त के साथ 826.5 रुपये हुआ। तांबा मई 1350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 92 पैसे के सुधार के साथ 8.54 रुपये हुआ। जस्ता मई 410 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 7 पैसे की नरमी के साथ 0.13 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल जून 10000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 46.6 रुपये की बढ़त के साथ 843.6 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मई 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.35 रुपये की गिरावट के साथ 5.3 रुपये हुआ।

सोना मई 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 64.5 रुपये की गिरावट के साथ 228.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मई 250000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 710.5 रुपये की गिरावट के साथ 1001 रुपये हुआ। तांबा मई 1340 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 5.17 रुपये की गिरावट के साथ 8.87 रुपये हुआ। जस्ता मई 365 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 15 पैसे की नरमी के साथ 1.4 रुपये हुआ।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष 'वन नेशन, वन इलेक्शन' को लेकर अपने विचार व्यक्त किए

▶▶ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की संकल्पना 'वन नेशन, वन इलेक्शन' से साकार होगी : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- ▶▶ लगातार होते चुनावों से सरकारी तंत्र की कार्यक्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है
- ▶▶ राज्य में काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों को अपना वोट देने के लिए बार-बार अपने गृह राज्य में जाना पड़ता है, जिससे उत्पादन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है
- ▶▶ देश की आजादी के बाद लगातार 15 वर्षों तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए

गांधीनगर : 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर राज्यों की प्रतिक्रियाएं और सुझाव लेने के लिए गुजरात के दौरे पर आई संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के समक्ष मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की संकल्पना 'वन नेशन, वन इलेक्शन' से साकार होगी।

बुधवार को गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में जेपीसी द्वारा आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने अपने विचार व्यक्त किए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों से अधिक समय में हम अनेक संवैधानिक सुधारों के गवाह बने हैं, जिनमें 'वन नेशन, वन इलेक्शन', 'वन नेशन, वन टैक्स', 'वन नेशन, वन राशन कार्ड', 'वन नेशन, वन ग्रिड', और 'वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन' जैसी पहलें शामिल हैं। इन सभी सुधारों से प्रशासन में एकरूपता आई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर देश की विकास यात्रा में सुशासन के साथ-साथ स्पष्ट नीति और जनभागीदारी बहुत ही आवश्यक है, और इसके लिए 'वन नेशन, वन इलेक्शन' देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया में इस बात का भी जिक्र किया कि देश की आजादी के बाद लगातार 15 वर्षों तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण वह व्यवस्था टूट गई।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि गुजरात जैसे विकसित राज्य में दूसरे प्रदेशों के लाखों श्रमिक काम करते हैं। लगातार होने वाले चुनावों के कारण इन श्रमिकों के एक बड़े वर्ग को अपना वोट देने के लिए अपने गृह राज्य में जाना पड़ता है। इसके चलते, गुजरात राज्य के उत्पादन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।

उन्होंने इन मुद्दों पर विस्तार से रोशनी डालते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया में बडो पैमाने पर लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनपावर की जरूरत पड़ती है। इसके कारण ज्यादातर सरकारी तंत्र चुनावी कार्यों में व्यस्त रहता है। इसके अलावा, इन सबके पीछे होने वाला खर्च भी राज्य सरकार को वहन करना पड़ता है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस संवैधानिक सुधार को राष्ट्रहित से जुड़ा बताया और कहा कि भारत के जीवंत लोकतंत्र में जनता की भागीदारी बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों का उत्साह बढ़ाने में यह सुधार महत्वपूर्ण साबित होगा।

मुख्यमंत्री ने यह विचार भी व्यक्त किया कि इस मुद्दे पर संबंधित पक्षों की प्रतिक्रियाएं सुनने के लिए आई जेपीसी को 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के मुद्दे पर अन्य राजनीतिक दलों के विविध विचार भी जानने को मिलेंगे, और इन सभी विचारों को एकसूत्र में बांधने से एक नया मार्ग मिलेगा।

महंगाई नए उच्च स्तर पर: तेल-गैस संकट के बीच अप्रैल में थोक महंगाई दर 8.3% तक पहुंच गई

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

देश में महंगाई का बादशाह मुस्कुराते हुए लोगों को आर्थिक रूप से निगलने को तैयार है। ऐसे में जीवन की सभी आवश्यक वस्तुएं महंगी होती जा रही हैं। मार्च में जिन वस्तुओं की कीमतें सामान्य थीं, अप्रैल में उनमें बेतहाशा वृद्धि हो गई। और मई में भी यह वृद्धि रॉकेट की रफ्तार से जारी है, जबकि देश के करोड़ों आम नागरिकों का जीवन दिन-प्रतिदिन और भी कठिन होता जा रहा है। और आने वाले दिनों का तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच, तेल और गैस की कमी के कारण आने वाले दिनों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। आम आदमी के लिए पैदा हुई कठिन परिस्थितियों से हर कोई वाकिफ है, खासकर खाना पकाने की गैस की कमी के कारण। इस दौरान, ईंधन, बिजली और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण अप्रैल में देश में थोक मुद्रास्फीति दर 8.3% दर्ज की गई, जबकि मार्च में यह 3.88% थी। स्पष्ट है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति का असर अब घरेलू बाजार पर भी पड़ने लगा है।

इस स्थिति में, यदि खाद्य पदार्थों से लेकर अन्य दैनिक आवश्यक वस्तुओं तक की कीमतें बेकाबू हो जाती हैं, तो इससे न केवल अन्य जगहों पर बल्कि यहाँ भी अराजकता फैल जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के कारण उत्पन्न ऊर्जा संकट को देखते हुए, केंद्र सरकार के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल और गैस उत्पादक देशों के साथ संवाद शुरू करना और देश के सामने मौजूद गंभीर कठिनाइयों को दूर करने के लिए सक्रिय कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है।

बिहार में कानून का राज स्थापित विपक्ष फैला रहा भ्रम: नवल शर्मा

पटना। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नवल शर्मा ने कहा है कि बिहार में कानून-व्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है और राज्य में सुशासन का प्रभाव पहले से अधिक दिखाई दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा स्थापित सुशासन की व्यवस्था को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनी है।

नवल शर्मा ने कहा कि बिहार सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता कानून का राज स्थापित रखना है और इसके लिए पुलिस प्रशासन को पूरी तरह सक्रिय और सशक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में अपराध नियंत्रण के लिए लगातार विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनमें अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना था कि सरकार की सख्त नीति के कारण आपराधिक तत्वों में भय का माहौल बना है और आम जनता पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित महसूस कर रही है।

जदयू प्रवक्ता ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर अनावश्यक भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर केवल राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि प्रशासन लगातार सक्रियता के साथ काम कर रहा है और हर आपराधिक घटना पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने कहा कि सुशासन के कारण बिहार में न केवल कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, बल्कि विकास कार्यों को भी नई गति मिली है। सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सरकार की नीतियों का सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। उनका कहना था कि राज्य में अब ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे और उसे प्रशासन पर पूरा भरोसा हो।

नवल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर लगातार काम कर रही है। अपराध नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के लिए तकनीक का उपयोग बढ़ाया जा रहा है और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति स्पष्ट है कि किसी भी अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्राकृतिक खेती से डांग के किसान आनंद ले रहे हैं स्ट्रॉबेरी की मिठास का, प्रति हेक्टेयर हो रही है 7 से 8 लाख रुपए तक की कमाई

▸▸ डांग बना गुजरात का स्ट्रॉबेरी हब : विंटर डॉन, अर्ली विंटर, कैमेरोजा, स्वीट चार्ली, नाभिला सहित 9 किस्मों की होती है खेती

▸▸ डांग में स्ट्रॉबेरी के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि, वर्ष 2025-26 में उत्पादन 233 मीट्रिक टन पहुँचने की संभावना

गांधीनगर : गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में गुजरात का कृषि एवं बागवानी क्षेत्र अभूतपूर्व परिवर्तन का साक्षी बना है। किसान-केंद्रित नीतियों, सिंचाई सुविधाओं तथा टेक्नोलॉजी के समन्वय से राज्य में विशेषकर बागवानी खेती को बहुत प्रोत्साहन मिला है। किसान परंपरागत खेती के बजाय बागवानी फसलों की खेती कर मोटी कमाई कर रहे हैं। गुजरात के स्ट्रॉबेरी हब के रूप में उभरे डांग जिले ने इस परिवर्तन का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। अनुकूल जलवायु, प्राकृतिक खेती और बढ़ती बाजार मांग के कारण जिले में स्ट्रॉबेरी की खेती में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2022-23 में जहाँ 20 हेक्टेयर में स्ट्रॉबेरी की खेती होती थी, वहीं 2025-26 में बढ़कर 33 हेक्टेयर तक पहुँचने की संभावना है।

वर्ष 2025-26 में स्ट्रॉबेरी का उत्पादन 233 मीट्रिक टन पहुंचने की संभावना

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में डांग को देश का पहला प्राकृतिक (खेती करने वाला) जिला घोषित किया गया था। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन मिलने से किसानों ने स्ट्रॉबेरी उत्पादन में उल्लेखनीय सफलता पाई है। स्ट्रॉबेरी का उत्पादन वर्ष 2022-23 में 140 मीट्रिक टन से बढ़कर 2024-25 में 196 मीट्रिक टन तक पहुँचा है, जबकि वर्ष 2025-26 में यह आँकड़ा 233 मीट्रिक टन तक पहुँचने का अनुमान है।

डांग जिले की जलवायु तथा भूमि स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है। स्ट्रॉबेरी की फसल पानी की उचित निकासी कर सकने वाली, जैविक तत्वों से भरपूर, रेतीली एवं दोमट भूमि में बढ़िया तरीके से होती है। इस जमीन का पीएच 5.5 से 7.0 के बीच होता है और यह हानिकारक सूक्ष्मजीवों से मुक्त मानी जाती है। इसके अलावा; अनुकूल वर्षा एवं शीतल वातावरण स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए अधिक लाभदायी बनते हैं। स्ट्रॉबेरी अल्पकालिक फसल होने के कारण उसमें फल आने में तथा फल बनने के लिए 8 से 12 घण्टे सूर्य प्रकाश आवश्यक है, जबकि दिन में 22 से 25 और रात में 7 से 13 डिग्री सेल्सियस तापमान इस फसल के लिए आदर्श माना जाता है।

प्राकृतिक खेती से किसान आनंद ले रहे हैं स्ट्रॉबेरी की मिठास का

गुजरात सरकार के बागवानी विभाग द्वारा प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन और मार्गदर्शन मिलने के कारण किसान प्राकृतिक खेती की ओर मुड़ रहे हैं। डांग को प्राकृतिक जिला घोषित किए जाने के बाद यहाँ प्राकृतिक पद्धति से होने वाली स्ट्रॉबेरी की खेती को नई पहचान मिली है। यहाँ किसान विंटर डॉन, अर्ली विंटर, कैमेरोजा, स्वीट चार्ली, नाभिला, नाबाडी, सेल्वा, बेलरूबी तथा पजेरो जैसी 9 किस्मों की स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। इसमें भी विंटर डॉन किसानों में सबसे लोकप्रिय है, क्योंकि दिसंबर से फरवरी-मार्च तक उसकी अच्छी उपज मिलती है। डांग में ग्रामीण स्तर पर स्ट्रॉबेरी की खेती के विशिष्ट क्लस्टर विकसित हुए हैं। जिला मुख्यालय आहवा तहसील में भूरापाणी, बोरीगवठा, गलकुंड, कोटमदार, मालेगाँव, डभास, सोनुनिया तथा वनर गाँवों में बड़े पैमाने पर स्ट्रॉबेरी की खेती होती है, जबकि वघई तहसील में कंचनपाडा, घोडवहाल, मुरंबी एवं आसपास के गाँवों में स्ट्रॉबेरी की खेती उल्लेखनीय प्रमाण में हो रही है।

सरकार किसानों को देती है 55 से 75 प्रतिशत तक की सहायता

केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा स्ट्रॉबेरी के पौधे तथा अन्य कृषि खर्च पर 55 से 75 प्रतिशत तक सहायता दी जाती है। इसके अलावा; प्लास्टिक कवर, मल्चिंग मटीरियल, प्लास्टिक क्रेट, पैकिंग मटीरियल तथा मिनी ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टिवेटर एवं ट्रॉली जैसे कृषि मशीनरी-उपकरण के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। बागवानी विभाग द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों तथा शैक्षणिक यात्राओं से किसान आधुनिक कृषि पद्धतियाँ अपनाकर अधिक उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं।

स्ट्रॉबेरी की खेती से किसानों को प्रति हेक्टेयर 7 से 8 लाख रुपए तक की आय हो रही है

डांग के कई किसान आज स्ट्रॉबेरी की खेती कर आर्थिक प्रगति कर रहे हैं। पहले ये किसान समीपस्थ औद्योगिक क्षेत्रों तथा महाराष्ट्र के खेतों में मजदूरी करके जीवन निर्वाह करते थे। स्थानीय स्तर पर वे डांग, नागली, उड़द तथा वराई जैसी परंपरागत फसलों की खेती करते थे, जिसमें आय सीमित थी, लेकिन स्ट्रॉबेरी की खेती की ओर मुड़ने के बाद किसानों को अब प्रति हेक्टेयर वार्षिक लगभग 7 से 8 लाख रुपए तक की कमाई हो रही है। शुरुआत में सापुतारा तथा आहवा जैसे स्थानीय बाजारों में बिकने वाली स्ट्रॉबेरी अब अहमदाबाद, सूरत तथा भरूच जैसे बड़े बाजारों तक पहुँच रही है और साथ ही स्थानीय लोगों को मौसमी रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं।

सरकारी मशीनरी द्वारा राज्य के जलाशयों की मजबूती-जल भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए तीन वर्षों में लगभग 2.21 करोड़ घन मीटर मिट्टी कार्य पूर्ण किया गया : जल संसाधन राज्य मंत्री श्री ईश्वरसिंह पटेल

अन्य उपलब्धियां

- ▸▸ विभाग द्वारा लगभग 123 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र अर्थात 4,200 किलोमीटर लंबाई में अनुपयोगी वनस्पति हटाई गई
- ▸▸ तीन वर्षों के दौरान कुल 1,474 साइट पर कार्य पूर्ण करने के लिए औसतन 88 से 96 मशीनरी का उपयोग
- ▸▸ नदी, नाला, तालाब, कैनाल आदि की मूल स्थिति बहाल करने के लिए जल संसाधन विभाग सतत कार्यरत

गांधीनगर : किसानों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक सिंचाई सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के साथ-साथ सिंचाई व्यवस्था को आधारभूत स्तर पर अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष विशेष अभियान चलाया जाता है। इसी के अंतर्गत जल संसाधन विभाग के अधीन सरकारी मशीनरी द्वारा राज्य में जलाशयों की मजबूती तथा जल भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए पिछले तीन वर्षों में लगभग 2.21 करोड़ अर्थात 221.37 लाख घन मीटर मिट्टी कार्य पूर्ण किया गया है।

जल संसाधन राज्य एवं जल आपूर्ति मंत्री श्री ईश्वरसिंह पटेल ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान 203 लाख घन मीटर मिट्टी कार्य के नियोजन के मुकाबले 221.37 लाख घन मीटर मिट्टी कार्य पूर्ण कर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में इस विभाग ने नया मील का पत्थर स्थापित किया है।

जल संसाधन राज्य मंत्री श्री ईश्वरसिंह पटेल ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि लगभग 123 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र अर्थात 4,223 कि.मी. लंबाई में किए गए ढांचागत सुधार कार्यों के अंतर्गत विभिन्न बांधों, नहरों, तालाबों आदि पर उगी झाड़ियां एवं अनुपयोगी वनस्पति हटाने का कामकाज भी पिछले तीन वर्षों में पूर्ण किया गया है।

मंत्री ने जोड़ा कि इस अवधि के दौरान तीन वर्षों में कुल 1,474 साइटों पर कार्य पूर्ण किया गया है। इन कार्यों को पूर्ण करने में औसतन 88 से 96 सरकारी मशीनरी कार्यरत रही। इस अभियान के पूर्ण होने से राज्य के जलाशयों की मजबूती के साथ-साथ कैनाल के आयुष्य तथा जल वहन क्षमता में वृद्धि होती है।

श्री पटेल ने गर्व के साथ कहा कि राज्य के जलाशयों, नहरों, नदियों, चेकडैम, नालों एवं तालाबों को गहरा कर गाद हटाने, कैनाल एवं ड्रेनेज व्यवस्था की सफाई, रखरखाव और पुनर्स्थापन संबंधी कार्य, बाढ़ के पानी में बाधा बनने वाले अवरोधों को हटाने तथा बाढ़ राहत से जुड़ी आकस्मिक और आवश्यक कामकाज आधुनिक हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी के सुव्यवस्थित उपयोग से किया जाता हैं।

मंत्री ने कहा कि सिंचाई यांत्रिक वृत्त वडोदरा एवं अहमदाबाद के अंतर्गत विभिन्न जिलों में कार्यरत कार्यालय राज्य सरकार के सिंचाई विभाग की हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के संवर्धन और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन प्रमुख कार्यों में जलाशयों का संवर्धन, नहरों, नदियों और ड्रेनेज का रखरखाव, मिट्टीबंध एवं तटबंधों का मजबूतीकरण, क्षार प्रवेश रोकथाम-सुधार तथा विशेष इंजीनियरिंग कार्यों के अंतर्गत कॉफर डैम का निर्माण शामिल है। इस अभियान को पूर्ण करने के लिए विभाग का पूरा स्टाफ एवं श्रमिक भौगोलिक चुनौतियों और विषम मौसम में भी दिन-रात कार्यरत रहता है।

राज्य में पिछले तीन वर्षों में 2.21 करोड़ घन मीटर से अधिक मिट्टी कार्य तथा 4,000 किमी से अधिक लंबाई में सफाई कार्य यह सिद्ध करता है कि राज्य सरकार जल प्रबंधन के विषय में अत्यंत गंभीर और कार्यक्षम है। जल राज्य संसाधन मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी वर्षों में भी आधुनिकीकरण और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सिंचाई यांत्रिक विभाग गुजरात को वॉटर सरप्लस राज्य बनाने की दिशा में अग्रसर रहेगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल रूस के अस्ट्राखान और गुजरात के बीच प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई सहयोग यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अस्ट्राखान के गवर्नर श्री इगौर बाबूश्किन के साथ वर्चुअल बैठक

▸▸ दोनों प्रदेश व्यापार, शिक्षा और शिप बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमत

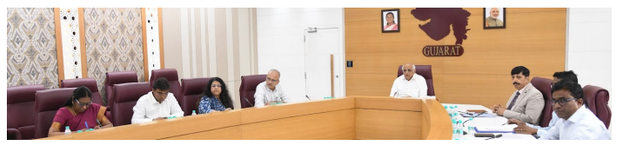

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को गांधीनगर से रूस के अस्ट्राखान प्रांत के गवर्नर श्री इगौर बाबूश्किन के साथ वर्चुअल बैठक की और दोनों प्रदेशों के बीच भागीदारी को और भी मजबूत करने पर चर्चा-विमर्श किया।

इस बैठक में दोनों प्रदेश व्यापार, शिक्षा और शिप बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग के लिए सहमत हुए।

इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने इस बैठक में अंतरराष्ट्रीय नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (आईएनएसटीसी) के विकास के हिस्से के तौर पर परिवहन और लॉजिस्टिक्स में सहयोग प्रदान करने की भी तत्परता दिखाई और राज्य में मौजूद जहाज निर्माण के अवसरों पर भी प्रकाश डाला।

उल्लेखनीय है कि गुजरात और अस्ट्राखान के बीच 2001 में प्रोटोकॉल सहयोग को लेकर किया गया करार 6 नवंबर तक लागू है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2003 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में ऑयल और गैस, शिप बिल्डिंग, फूड इंडस्ट्रीज, मत्स्य पालन, दवाइयों और फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता करार किए थे। इसके अलावा, मानव संसाधान विकास के तहत शिक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को लेकर भी समझौता करार किए गए थे। इस वर्चुअल बैठक में इसकी भी चर्चा की गई।

उल्लेखनीय है कि गत फरवरी में अस्ट्राखान प्रांत के विदेश मामलों के मंत्री के साथ हुई वर्चुअल बैठक में अस्ट्राखान के विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में निवेश करने, अस्ट्राखान प्रांत की यूनिवर्सिटियों के साथ गुजरात की कृषि यूनिवर्सिटी, एनर्जी यूनिवर्सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू करने के संबंध में भी चर्चा की गई थी।

इसके अतिरिक्त, मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के साथ समुद्री परिवहन से संबंधित पाठ्यक्रमों का आदान-प्रदान करने को लेकर भी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

इस बैठक में दोनों प्रदेशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को लेकर भी चर्चा हुई और परस्पर प्रतिनिधिमंडल भेजने के लिए आमंत्रण दिया गया.

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री एम.के. दास, उद्योग एवं खान विभाग की अपर मुख्य सचिव सुश्री ममता वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार और अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे सहित राज्य के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे।

रैपिडो कस्टमर केयर के नाम पर साइबर धोखाधड़ी: APK लिंक पर क्लिक करने के बाद महिला के खाते से 50 हजार की चोरी

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। आजकल सरकार, मीडिया, पुलिस और बैंकों द्वारा बार-बार जनता को डिजिटल साइबर घोटालों के बारे में जागरूक करने के बावजूद, लोग अभी भी इन घोटालों में अपना पैसा क्यों गंवा रहे हैं? ऐसा ही एक मामला दक्षिण मुंबई में सामने आया है। ब्रीच कैंडी के पास रहने वाली 41 वर्षीय गुजराती महिला ने अपने मोबाइल फोन से रैपिडो कंपनी का नंबर खोजने की कोशिश की और उसके बैंक खाते से 50,000 रुपये निकाल लिए गए। इस मामले में गामदेवी पुलिस ने कल शिकायत दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

महिला के पिता, जो एक पर्सनैलिटी ट्रेनर हैं, 13 अप्रैल को रैपिडो कैब में अपना मोबाइल फोन भूल गए थे। अपने पिता की मदद करने के लिए महिला ने गूगल पर रैपिडो के कस्टमर केयर नंबर की खोज की। वहां मिले नंबरों में से एक पर संपर्क करने वाले साइबर अपराधियों ने उसे अपने जाल में फंसा लिया और कुछ ही मिनटों में दो लेनदेन के माध्यम से महिला के बैंक खाते से कुल 50,000 रुपये निकाल लिए। पैसे की वसूली के लिए आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

फिर, ग्राहक सहायता के बहाने, साइबर अपराधियों ने महिला के व्हाट्सएप पर customersupport.apk नाम का एक लिंक भेजा और टैक्सी ट्रैक करने के नाम पर उससे 10 रुपये भेजने को कहा। जैसे ही महिला ने इस लिंक पर क्लिक किया, उसका मोबाइल हैक हो गया और कुछ देर के लिए हैंग हो गया। शक होने पर महिला ने फोन बंद करके दोबारा चालू किया, तब तक उसे एक संदेश मिला कि उसके खाते से पैसे कट चुके हैं।

महिला ने तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। हमने शिकायत दर्ज कर ली है और आगे की जांच शुरू कर दी है। इसलिए सावधान रहें।

साबरमती-जोधपुर-साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस का जैसलमेर तक विस्तार

रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की मांग एवं सुविधा के लिए ट्रेन संख्या 20486/20485 साबरमती-जोधपुर-साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस का जैसलमेर तक विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन जोधपुर से आगे ओसियां, फलोदी एवं रामदेवरा स्टेशनों पर ठहरेगी। इस ट्रेन का विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 20486/20485 साबरमती-जैसलमर-साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 20486 साबरमती-जैसलमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 23 मई 2026 से प्रतिदिन साबरमती से प्रातः 07.00 बजे प्रस्थान कर बिना किसी परिवर्तन के जोधपुर पहुंचेगी। इसके बाद यह ट्रेन ओसियां स्टेशन पर 15.59 बजे आगमन एवं 16.02 बजे प्रस्थान, फलोदी जंक्शन पर 17.28 बजे आगमन एवं 17.33 बजे प्रस्थान तथा रामदेवरा स्टेशन पर 18.25 बजे आगमन एवं 18.28 बजे प्रस्थान करेगी तथा 20.30 बजे जैसलमेर पहुंचेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 20485 जैसलमेर-साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस 23 मई 2026 से जैसलमेर से प्रतिदिन प्रातः 06.30 बजे प्रस्थान करेगी तथा रामदेवरा स्टेशन पर 07.50 बजे आगमन एवं 07.53 बजे प्रस्थान, फलोदी जंक्शन पर 09.10 बजे आगमन एवं 09.15 बजे प्रस्थान तथा ओसियां स्टेशन पर 10.02 बजे आगमन एवं 10.05 बजे प्रस्थान करेगी।

इस ट्रेन का साबरमती और जोधपुर के बीच आगमन-प्रस्थान समय यथावत रहेगा।

ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना की विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

जेतलसर जंक्शन रेलवे स्टेशन का तेजी से हो रहा कायाकल्प यात्रियों को शीघ्र मिलेंगी विश्वस्तरीय आधुनिक सुविधाएं

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के अंतर्गत स्थित जेतलसर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और आधुनिक अवसंरचना विकास के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर पुनर्विकास कार्य तीव्र गति से प्रगति पर हैं। इन कार्यों के पूर्ण होने के बाद जेतलसर जंक्शन एक आधुनिक, सुगम, सुरक्षित एवं यात्री-अनुकूल रेलवे स्टेशन के रूप में नई पहचान स्थापित करेगा।

दिनांक 19 मई 2026 (मंगलवार) को जेतलसर के प्रतिनिधियों के साथ मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा एवं संबंधित शाखाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जेतलसर स्टेशन से संबंधित विभिन्न विकासात्मक विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर बताया गया कि जेतलसर जंक्शन को प्रतिष्ठित अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया जा चुका है तथा विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाएगा।

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि जेतलसर स्टेशन के लिए मोबाइल एआरटी (Accident Relief Train) को स्वीकृति मिल चुकी है तथा यहां नया टीआरडी (Traction Distribution) डिपो स्थापित किया जा रहा है, जिससे रेल संचालन एवं अनुरक्षण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ता मिलेगी।

पूर्व में लॉबी के स्थानांतरण को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करते हुए स्पष्ट किया गया कि रेलवे लॉबी जेतलसर स्टेशन पर संचालित होती रहेगी। और भविष्य में यहां कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि कर इसे और अधिक कार्यक्षम बनाया जाएगा।

स्टेशन पुनर्विकास योजना के अंतर्गत स्टेशन परिसर के सौंदर्यीकरण, विस्तारित पार्किंग क्षेत्र, आधुनिक आगमन एवं प्रस्थान प्लाज़ा, उन्नत प्रकाश व्यवस्था, प्लेटफॉर्मों पर बड़े आकार के शेड, स्वच्छ एवं दिव्यांगजन-अनुकूल शौचालय, पेयजल बूथ तथा वाटर कूलर जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। स्टेशन भवन के समीप यात्रियों एवं रेल कर्मचारियों के लिए पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है।

यात्रियों की सुरक्षित एवं सुगम आवाजाही के लिए प्लेटफॉर्म संख्या 2/3 तथा 4/5 को जोड़ने वाले नए फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) का निर्माण मार्च 2026 में सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। यह संरचना प्लेटफॉर्मों के बीच आवागमन को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बना रही है।

स्टेशन पर लिफ्ट सुविधा का कार्य अंतिम चरण में है। विद्युत विभाग द्वारा आवश्यक निरीक्षण पूरा कर लिया गया है तथा परीक्षण एवं प्रमाणन प्रक्रिया पूर्ण होते ही इसे यात्रियों के उपयोग के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। इससे वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं तथा दिव्यांगजन यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा।

यात्रियों को ट्रेनों की जानकारी त्वरित रूप से उपलब्ध कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कोच इंडिकेशन बोर्ड की स्थापना का कार्य जून 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। प्लेटफॉर्म संख्या 3 तथा 4/5 के विस्तार का कार्य मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्टेशन पर आधुनिक सीसीटीवी कैमरों की स्थापना का कार्य भी अंतिम चरण में है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।

जलापूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नए ओवरहेड वाटर टैंक का निर्माण मई 2026 में पूरा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 150 लीटर क्षमता वाले आधुनिक वाटर कूलर की व्यवस्था पहले ही उपलब्ध करा दी गई है। अतिरिक्त यात्री सुविधाओं तथा रखरखाव कार्यों के लिए नए भवनों और स्टोर्स के निर्माण की प्रक्रिया भी प्रगति पर है।

दृष्टिबाधित यात्रियों की सुविधा के लिए टैक्टाइल गाइड पाथ का कार्य मार्च 2026 में पूर्ण किया जा चुका है, जिससे उन्हें स्टेशन परिसर में सुरक्षित एवं स्वतंत्र रूप से मार्गदर्शन प्राप्त हो सकेगा।

जेतलसर जंक्शन पर चल रहे ये सभी विकास कार्य भारतीय रेल की यात्री सुविधा, संरक्षा, सुरक्षा, समावेशिता और आधुनिकता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के उपरांत यात्रियों को महानगरों के आधुनिक रेलवे स्टेशनों के समकक्ष सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे उनका यात्रा अनुभव अधिक आरामदायक, सुरक्षित और सुखद बनेगा।

मध्यस्थता और मध्यस्थता में क्षमता निर्माण के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान को मजबूत करने पर ब्रिक्स के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक

भारत BRICS 2026 की अध्यक्षता के तहत, कानूनी मामलों के विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार ने वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) पर सहयोग को और गहरा करने के लिए गांधीनगर, गुजरात में 19 से 20 मई 2026 तक वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक संपन्न की। यह बैठक हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी, जिसमें ब्राजील, चीन, भारत, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के वरिष्ठ अधिकारियों ने भौतिक और ऑनलाइन दोनों तरह से भाग लिया था। "देशों के न्याय मंत्रियों की घोषणा" शीर्षक वाली संयुक्त घोषणा एक साझा सहमति के साथ संपन्न हुई, जिसे 21 से 22 मई 2026 तक गांधीनगर में आयोजित होने वाली ब्रिक्स न्याय मंत्रियों की बैठक में औपचारिक रूप से अपनाने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

इस बैठक में ब्रिक्स देशों के वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को एडीआर से संबंधित मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श के लिए एक साथ लाया गया। प्रतिनिधियों ने संस्थागत मध्यस्थता, मध्यस्थता सुधारों और वाणिज्यिक और सार्वजनिक क्षेत्र के विवादों में एडीआर की भूमिका पर चर्चा की, अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में अनुभवों, चुनौतियों और उभरते रुझानों पर प्रकाश डाला। यह सुलभ और प्रभावी साधनों के रूप में मध्यस्थता और मध्यस्थता को विस्तार, पेशेवर और मुख्यधारा में लाने के लिए ब्रिक्स देशों की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह परिणाम एक लचीला, अभिनव और सहकारी कानूनी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए ब्रिक्स सदस्यों के साझा दृष्टिकोण को दर्शाता है।